



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 279]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 25, 1987/ज्याइस्था 4, 1909

No. 279]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 25, 1987/JYAISTHA 4, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(विदेश कर प्रभाग)

नई दिल्ली, 25 मई, 1987

अधिसूचना

आयकर

मा. का. नि. 526(अ) :—भारत सरकार और चेकोस्लोवाक समाजवादी गणराज्य ने आय पर करों के सम्बन्ध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए एक करार सम्पन्न किया है; जैसा कि इस अधिसूचना के उपाखण्ड में निरूपित है;

और यतः उक्त करार के अनुच्छेद 28 की अपेक्षानुसार भारत और चेकोस्लोवाकिया में वे सभी अपेक्षाएँ पूरी कर ली गई हैं जो उक्त करार की कवच, भारत और चेकोस्लोवाकिया में विधि का रूप देने के लिए आवश्यक हैं;

और यतः करार के अनुच्छेद 28 की अपेक्षानुसार, उक्त दोनों सरकारों के बीच इस आशय की टिप्पणी की आदान-प्रदान हो गया है;

अतः इस, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 और कम्पनी (लाभ) अधिनियम, 1964 (1964 का 7) की धारा

24(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निवेदन देती है कि उक्त करार के सभी उपबन्ध भारत संघ में प्रभावी किए जाएंगे।

उपाखण्ड

भारत सरकार

और

चेकोस्लोवाकिया समाजवादी गणराज्य की सरकार

के बीच

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए करार

भारत सरकार और चेकोस्लोवाकिया समाजवादी गणराज्य की सरकार,
आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए करार करने की इच्छा से,
नॉले लिखे अनुसार सहमत हुई हैं।

अनुच्छेद—1

वैयक्तिक क्षेत्र

यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो किसी एक अथवा दोनों सविदाकारी राज्यों के निवासी हैं।

अनुच्छेद—२

करार के अन्तर्गत आने वाले कर

(क) यह करार जिन करों पर लागू होगा वे हैं :—

(क) भारत के मामले में,

(1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन लगाया गया आयकर जिसमें आयकर पर कोई अधिभार भी शामिल है।

(2) कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) के अधीन लगाया गया अतिकर,

(जिसे इसके बाद "भारतीय कर" कहा गया है)।

(ख) चेकोस्लोवाकिया के मामले में :

(1) लाभों पर कर,

(2) मजदूरी कर,

(3) साहित्यिक तथा कलात्मक कार्यकलापों से आय पर कर,

(4) कृषिकर,

(5) जनसंख्या आय पर कर,

(6) गृह कर,

(जिसे इसके बाद "चेकोस्लोवाकिया कर" कहा गया है)।

2. यह करार किसी भी सम्मेलन अथवा सारतः इसी प्रकार के उन करों पर भी लागू होगा जो वर्तमान करार पर हस्ताक्षर किये जाने की तारीख के पश्चात् इस अनुच्छेद के पैराग्राफ-1 में उल्लिखित करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर दोनों ही संविदाकारी राज्यों द्वारा लगाये जाएंगे।

3. प्रत्येक वर्ष के अन्त में, संविदाकारी राज्यों के मक्षम प्राधिकारी अपने-अपने कानूनों में उन करों के संबंध में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तनों से एक दूसरे को अधिसूचित करेंगे जो इस करार के विषय हैं और संगत अधिनियमों और विनियमों की प्रतियाँ भेजेंगे।

अनुच्छेद—३

सामान्य परिभाषाएँ

1. इस करार में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो :

(क) "भारत" शब्द से अभिप्रेत है भारत का राज्य क्षेत्र और उसमें प्रादेशिक समुद्र और उसके ऊपर का आकाशी क्षेत्र तथा कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र शामिल है, जिसमें भारतीय कानून के अनुसार तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून/समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के अनुसार भारत के सर्वभौम अधिकार, अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधिकार हों;

(ख) "चेकोस्लोवाकिया" शब्द से अभिप्रेत है चेकोस्लोवाकिया समाजवादी गणराज्य,

(ग) "एक संविदाकारी राज्य" और "दूसरे संविदाकारी राज्य" शब्दों से, संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार, भारत अथवा चेकोस्लोवाकिया अभिप्रेत है,

(घ) "कर" शब्द से, संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार, भारतीय कर अथवा चेकोस्लोवाकियाई कर अभिप्रेत है;

(ङ) "व्यक्ति" शब्द का अर्थ बड़ी होगा जो अलग-अलग संविदाकारी राज्यों में लागू कराधान कानूनों में इसके लिए दिया गया है,

(च) "कम्पनी" शब्द से कोई ऐसा निर्गमित निकाय अथवा कोई ऐसा मन्ता अभिप्रेत है, जो अलग-अलग संविदाकारी राज्यों के कराधान कानूनों के अन्तर्गत एक कंपनी के रूप में मान्य होती है;

(छ) "एक संविदाकारी राज्य का उद्यम" तथा "दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम" शब्दों से क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के किसी

निवासी द्वारा संचालित उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा संचालित उद्यम अभिप्रेत है;

(ज) "मक्षम प्राधिकारी" शब्दों से अभिप्रेत है, भारत में मामल में केन्द्रीय सरकार का त्रिम मन्त्रालय (राजस्व विभाग), और चेकोस्लोवाकिया के मामले में चेकोस्लोवाकिया समाजवादी गणराज्य का वित्त मंत्री अथवा उसका विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि।

2. संविदाकारी राज्यों में से किसी एक राज्य द्वारा इस करार के उपबंधों के प्रवर्तन में, किसी भी पक्ष का, जो यहाँ परिभाषित नहीं हुआ हो, संदर्भ की अपेक्षा अपेक्षा नहीं होने पर, वही अर्थ होगा जो उस संविदाकारी राज्य में लागू उन पर कानूनों के अन्तर्गत होता है जो इस करार के विषय हैं।

अनुच्छेद—४

आर्थिक अधिकार

1. इस करार के प्रयोजनार्थ, "संविदाकारी राज्य का निवासी" पद से अभिप्रेत किसी भी ऐसे व्यक्ति से है जो उस संविदाकारी राज्य के कराधान कानूनों के अनुसार उस संविदाकारी राज्य का निवासी है।

2. जहाँ पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो वहाँ इस करार के प्रयोजनार्थ उसका निवासीय प्रास्थिति निम्नलिखित नियमों के अनुसार तय की जाएगी :—

(क) वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसे कोई स्थायी गृह उपलब्ध हो। यदि उसे दोनों संविदाकारी राज्यों में स्थायी गृह उपलब्ध हों तो यह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर होंगे (इसके बाद जिसे "उसके महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र" कहा गया है)।

(ख) यदि उस संविदाकारी राज्य का प्रबन्धन नहीं किया जा सकता हो तो उसके महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र हो, अथवा यदि उसे किसी भी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी गृह उपलब्ध नहीं हो, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें वह आदतन रहता हो;

(ग) यदि वह दोनों ही राज्यों में आदतन रहता हो अथवा उनमें से किसी भी राज्य में आदतन नहीं रहता हो तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसका वह राष्ट्रिक है;

(घ) यदि वह दोनों संविदाकारी राज्यों का राष्ट्रिक है अथवा उनमें से किसी का भी राष्ट्रिक नहीं है तो संविदाकारी राज्यों के मक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करेंगे।

3. जहाँ व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति पैराग्राफ-1 के उपबंधों के कारण दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो तो उसे उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका वास्तविक प्रबन्ध का स्थान स्थित है।

अनुच्छेद—5

स्थायी संस्थापन

1. इस करार के प्रयोजन के लिए, "स्थायी संस्थापन" पद से कारोबार का यह निश्चित स्थान अभिप्रेत है, जिसमें उद्यम का कारोबार सम्पूर्णतः अथवा अंशतः चलाया जाता है।

2. "स्थायी संस्थापन" पद में निम्नलिखित शामिल होंगे :

(क) प्रबन्ध का कोई स्थान;

(ख) कोई शाखा,

- (ग) कोई कार्यालय,
- (घ) कोई कारखाना,
- (ङ) कोई कार्यशाला अथवा भण्डारगार,
- (च) कोई खान, खदान तेल-क्षेत्र अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्क्रमण का अन्य स्थान;
- (छ) भवनविस्थल अथवा निर्माण अथवा संयोजन परियोजना अथवा उससे संबन्धित पर्यवेक्षी क्रियाकलाप जहाँ ऐसा स्थल, परियोजना अथवा पर्यवेक्षी क्रियाकलाप छः महीने से अधिक अवधि तक चलता है अथवा जहाँ ऐसी परियोजना अथवा पर्यवेक्षी क्रियाकलाप, मशीनरी अथवा उपस्कर के क्रिय में भ्रान्त्युत्पन्न होने की हालत में, ऐसा अवधि तक जारी रहता है जो छः महीने से अधिक नहीं हो, और ऐसी परियोजना अथवा पर्यवेक्षी क्रियाकलाप के लिए वेध प्रभार मशीनरी अथवा उपस्कर के क्रिय मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक हो।

3. "स्थायी संस्थापन" पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं किया जाएगा:

- (क) उद्यम के माल अथवा तिजारी माल के भण्डारण अथवा उसके प्रदर्शन के उद्देश्य के लिए ही सुविधाओं का प्रयोग;
- (ख) उद्यम के माल अथवा तिजारी सामान का स्टॉक केवल भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ रखना;
- (ग) दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा केवल संसाधित किए जाने के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा तिजारी माल का स्टॉक रखना;
- (घ) उद्यम के लिए माल अथवा तिजारी माल का केवल क्रय करने अथवा सूचना एकत्र करने के प्रयोजनार्थ कारोबार का कोई नियत स्थान रखना;
- (ङ) विज्ञापित करने, सूचना देने के लिए अथवा वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यकलाप, जो उद्यम के व्यापार अथवा कारोबार में अनिवार्य: प्रारंभिक अथवा सहायक स्वरूप के हों, के अन्तर्गत: प्रयोजनार्थ कारोबार के नियत स्थान रखना, लेकिन यदि वह उद्यम इसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न किसी प्रयोजन अथवा प्रयोजनों के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य में कारोबार का कोई अन्य नियत स्थान रखता है तो यह उपबंध लागू नहीं होगा।

4. अन्य संविदाकारी राज्य के उद्यम अथवा उद्यम की ओर से किसी संविदाकारी राज्य में कार्य करने वाले व्यक्ति को जो स्वतंत्र हैसियत के अधिकारी से भिन्न हो और जिस पर पैराग्राफ 5 लागू होता हो—प्रयोजित संविदाकारी राज्य में उस उद्यम का स्थायी संस्थापन माना जाएगा, यदि:

- (i) वह उस संविदाकारी राज्य में उस उद्यम अथवा उसकी ओर से बातचीत करने का तथा सविदाएं करने का प्राधिकार रखता है और उनका आवेदन प्रयोग करता है जब तक कि उसके क्रियाकलाप उस उद्यम के लिए माल अथवा पण्य वस्तुओं के क्रय तक ही सीमित न हो; अथवा
- (ii) वह प्रयोजित संविदाकारी राज्य में उद्यम के माल अथवा पण्य वस्तुओं का आवेदन रूप में ऐसा स्टॉक रखता है, जिसमें से वह व्यक्ति उद्यम अथवा उद्यम की ओर से नियमित रूप से माल अथवा पण्य वस्तुओं की डिमांडरी देता है; अथवा
- (iii) वह प्रयोजित संविदाकारी राज्य में अनिवार्य: अथवा लगातार अनिवार्य: उसी उद्यम के लिए अथवा उक्त उद्यम और तत्-नियमित अन्य उद्यमों के लिए, अथवा उसमें नियमित रूप से माल अथवा पण्य वस्तुओं के लिए व्यवहार रूप में धार्मिक प्राप्त करता है।

5. एक संविदाकारी राज्य के उद्यम या दूसरे संविदाकारी राज्य में मात्र इस कारण स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा कि वह एक दूसरे स

राज्य में किसी बलाज, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा वस्तुतः स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है, जहाँ ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार का काम सामान्य रूप से कर रहे हों।

6. कोई ऐसी कंपनी जो संविदाकारी राज्य की निवासी है अथवा ऐसी कंपनी द्वारा नियंत्रित है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य में (चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) व्यापार अथवा कारोबार चलाती है तो केवल इष्ट तथ्य से उन दोनों कंपनियों में से कोई भी एक कंपनी स्वतः दूसरी कंपनी का स्थायी संस्थापन नहीं बन जाएगी।

7. एक संविदाकारी राज्य का उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थायी संस्थापन माना जाएगा यदि वह दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसा कारोबार चलाता है जिसमें लोक मनोरंजनकर्ताओं (जैसे रंगमंच, थलचित्र, रेडियो अथवा टेलिविजन कलाकारों और संगीतज्ञों) अथवा खिलाड़ियों की सेवाएं प्रदान करना शामिल हो। जब तक कि ऐसी सेवाओं की व्यवस्था के साथ में उद्यम को प्रयोजित संविदाकारी राज्य की सरकार की सरकारी निधियों से प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः पूर्णतः अथवा पर्याप्त रूप से सहायता नहीं दी जाती है।

अनुच्छेद-6

अचल संपत्ति से आय

1. अचल संपत्ति से आय उस संविदाकारी राज्य में ही करावेय हो सकेगी जिसमें ऐसी संपत्ति स्थित हो।

2. "अचल संपत्ति" पद की परिभाषा उस संविदाकारी राज्य की विधि और व्यवहार के अनुसार की जाएगी, जिसमें संबंधित संपत्ति स्थित है। इस पद में किसी भी हालत में ये शामिल होंगे—अचल संपत्ति के उपसाधन के रूप में संपत्ति, कृषि और वन-संपत्ति में प्रयुक्त पशुधन तथा उपस्कर, ऐसे अधिकार, जिन पर भू-संपत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबंध लागू होते हैं। अचल संपत्ति को भोगने का अधिकार, खनिज संसाधनों, तेल के कुओं, खदानों तथा प्राकृतिक संसाधनों के निकालने के अन्य स्थानों को चलाने अथवा चलाने के हक रखने के कारण प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अथवा नियमित के अधिकार-अवययन तथा विमान अचल संपत्ति नहीं माने जाएंगे।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अचल संपत्ति के प्रत्यक्षतः प्रयोग से, किराए पर देने अथवा अन्य प्रकार के प्रयोग से होने वाली आय पर लागू होंगे।

4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 और 3 के उपबंध किसी उद्यम की अचल संपत्ति से होने वाली आय और व्यावहारिक सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल संपत्ति से होने वाली आय पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद-7

कारोबार के लाभ

1. संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार न करता हो। यदि कोई उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो तो उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है, परन्तु उसके केवल उसने अंग पर ही कर लगेगा जो (क) उस स्थायी संस्थापन (ख) उस दूसरे राज्य में उसी प्रकार की वस्तुओं अथवा तिजारी माल की बिक्री जो उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से की जाती है। अथवा (ग) उस दूसरे राज्य में की जाने वाली कारोबार संबंधी किसी भी अन्य गतिविधियों अथवा उसी प्रकार की गतिविधियों के कारण हुषा माना जा सकता है जो उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से की जाती हैं।

2. पैरा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए जहाँ किसी संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन द्वारा कारोबार करता हो तो प्रत्येक संविदाकारी राज्य में होने वाले लाभ का संस्थापन का ही लाभ समझा जाएगा, जिसे उसके द्वारा प्राप्त

होने की तब प्रेषणा की जाती जब वह उन्ही या वैसी ही परिस्थितियों में उन्हीं या वैसी ही कार्यों में लगा हुआ कोई निश्चित और भिन्न उद्यम होता और उस उद्यम के साथ पूर्णतया स्वतंत्र रूप से कारोबार करता जिसका वह स्थायी संस्थापन है। बहरहाल, जहाँ स्थायी संस्थापन के कारण हुए या माने जा सकने वाले लाभों की सही रकम निर्धारित नहीं की जा सकती हो अथवा उसका पता लगाना बहुत ही कठिन हो तो स्थायी संस्थापन के कारण हुए माने जा सकने वाले लाभों का अनुमान उपयुक्त आधार पर लगाया जाए।

3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण में उन व्ययों को, उस राज्य के कराधान कानूनों के उपबंधों के अनुसार तथा उनमें निर्धारित सीमा के अधीन रहते हुए, कटौतियों के रूप में स्वीकार किया जाएगा जो स्थायी संस्थापन के कारोबार के प्रयोजनों के लिए किए गए हों, जिनमें इस प्रकार किए गए कार्यकारी तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय शामिल है, चाहे वे उस राज्य में किए गए हों जहाँ स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा अन्यत्र। लेकिन, स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा उसके अन्य कार्यालयों में से किसी को (वास्तविक व्यय की प्रतियुक्तियों से भिन्न रूप में) भ्रदा की गयी रायल्टियों, पेटेंटों, जानकारी अथवा अन्य अधिकारों के प्रयोग के बदले फीस तथा इसी प्रकार की अन्य भ्रदायियों अथवा की गई विशिष्ट सेवाओं के लिए अथवा प्रबंध के लिए, अथवा बैंक उद्यम के मामलों को छोड़कर, स्थायी संस्थापन को उधार दिए गए धन पर ब्याज के रूप में, यदि कोई रकम अथवा की गयी हो, तो उनके संबंध में ऐसी किसी कटौती की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार, स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण में उन रकमों की हिसाब में नहीं लिया जाएगा, जो स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के प्रधान कार्यालय को या उसके अन्य कार्यालयों में से किसी को (वास्तविक व्यय की प्रतियुक्तियों से भिन्न रूप में) स्थायी संस्थापन द्वारा रायल्टियों, पेटेंटों, जानकारी अथवा अन्य अधिकारों के प्रयोग के बदले में फीस अथवा अन्य ऐसी ही भ्रदायियों के रूप में अथवा की गयी विशिष्ट सेवाओं के लिए अथवा प्रबंध के लिए कमीशन के रूप में, अथवा बैंक उद्यम के मामलों को छोड़कर, अन्य मामलों में, उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा उसके अन्य कार्यालयों में से किसी कार्यालय को उधार दिए गए धन पर ब्याज के रूप में उद्यम के प्रधान कार्यालय या उसके अन्य कार्यालयों में से किसी कार्यालयों को प्रभारित की गई हो।

4. कोई लाभ, मात्र इस कारण स्थायी संस्थापन को हुए नहीं माने जाएंगे कि उन स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के लिए, माल अथवा पण्य वस्तुएं खरीदी गई हैं।

5. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनों के लिए, स्थायी संस्थापन के कारण हुए माने जाने वाले लाभों को तब तक उसी पद्धति से वर्षानुवर्ष निर्धारित किया जाएगा जब तक कि उसके विरुद्ध कोई उपयुक्त तथा पर्याप्त कारण नहीं हो।

6. जहाँ लाभों में धाय की ये भवे शामिल हों जिनका इस करार के अन्य अनुच्छेदों में भ्रलग से विवेचन किया गया है, वहाँ उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे।

अनुच्छेद—8

बिमान-परिचयन

1. संविदाकारी राज्यों में से किसी एक संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा बिमान संचालन से प्राप्त धाय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में तब तक कर नहीं लगाया जाएगा जब तक कि वायुयान उस दूसरे संविदाकारी राज्य के स्वानों के बीच पूर्णतः अथवा मुख्यतः संचालित न किया जाता हो।

2. पैराग्राफ 1 बिमान परिचयन में लगे उद्यमों द्वारा किसी भी प्रकार के पूर्णों में भाग लेने के संबंध में इसी प्रकार लागू होगा।

3. पैराग्राफ 1 के प्रयोजन के लिए, अंतर्राष्ट्रीय यातायात में वायुयान संचालन से प्रत्यक्ष संबंध विधियों पर अंजाज को से वायुयान संचालन से होने वाली धाय माना जाएगा।

अनुच्छेद—9

अध्यायी उद्यम

जहाँ

(क) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है, अथवा

(ख) वे ही व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य के उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम के प्रबंध नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं,

और दोनों ही मामलों में दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी गई अथवा लगाई जाती हैं जो वैसी शर्तों से भिन्न हैं जैसी स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी गई होती वहाँ ऐसी कोई भी लाभ जो उन शर्तों के नहीं होने की हालत में उन उद्यमों में से एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता, परन्तु उन शर्तों के कारण प्राप्त नहीं हुआ, जो वह लाभ उस उद्यम के लाभों में सम्मिलित किया जा सकेगा और उस पर तदनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद—10

लाभांश

1. जो कम्पनी एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, उसके द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को भ्रदा किए गए लाभांश पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. तथापि, ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकता है जिसकी लाभांश देने वाली कम्पनी निवासी है, परन्तु यदि प्राप्तकर्ता लाभांशों का हितभागी स्वामी है, तो इस प्रकार लगाया गया कर नीचे बताई गई रकम से अधिक नहीं होगा :

(क) लाभांशों की सकल रकम का 15 प्रतिशत यदि हितभागी स्वामी, कोई ऐसी कम्पनी है जिसके पास लाभांश भ्रदा करने वाली कम्पनी के कम से कम प्रतिशत शेयर हों,

(ख) अन्य सभी मामलों में लाभांशों की सकल रकम का 25 प्रतिशत।

यह पैराग्राफ उन लाभांशों के संबंध में कम्पनी के कराधान को प्रभावित नहीं करेगा जिनमें से लाभांश भ्रदा किए जाते हैं।

3. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "लाभांशों" शब्द का अभिप्राय ऐसे शेयरों अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय से है, जो अण-दावे नहीं हों, जो लाभ में शामिल हों तथा अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त आय से है जिन पर उसी प्रकार की कराधान व्यवस्था लागू होती है जिस प्रकार उस राज्य के कानूनों द्वारा शेयरों से प्राप्त आय के मामलों में लागू होती है जिसकी वितरण करने वाली कम्पनी निवासी है।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि लाभांश का हितभागी स्वामी जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिनके लाभांश अदा करने वाली कम्पनी निवासी है, वहाँ स्थित किसी स्थायी संस्थान के माध्यम से व्यापार करता है अथवा उन दूसरे राज्य में, स्थित एक निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है और जिस धारिता के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती है, वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है। ऐसे मामलों में, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

5. जहाँ कोई कम्पनी जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, वहाँ वह दूसरा राज्य, कम्पनी द्वारा अदा किए गए लाभांशों पर किसी प्रकार का कर

नहीं लगाएगा सिवाए उस स्थिति के जब कि इस प्रकार के लाभों उस दूसरे राज्य के निवासी को अदा किए जाते हैं अथवा जिस धारणाधिकार के संबंध में लाभों अदा किए जाते हैं, वह उस दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन अथवा किसी निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध हो और न ही कम्पनी के अतिरिक्त लाभों पर कम्पनी के अतिरिक्त लाभों सम्बन्धी कर लगाएगा, चाहे अदा किए गए लाभों अथवा अतिरिक्त लाभों में, इस प्रकार के दूसरे राज्य में पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से उत्पन्न होने वाला लाभ अथवा आय शामिल क्यों न हो।

अनुच्छेद-11

ब्याज

1. एक सविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे सविदाकारी राज्य के निवासी को अदा किए जाने वाले ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. किन्तु इस प्रकार के ब्याज पर उस सविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिस राज्य में वह अर्जित होता है, किन्तु यदि प्राप्तकर्ता ब्याज का हितभागी स्वामी है तो इस प्रकार प्रभावित कर, ब्याज की सकल रकम के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. पैराग्राफ 2 के उपबन्धों के होते हुए भी—

(क) एक सविदाकारी राज्य में अर्जित होने वाले ब्याज पर उस राज्य में कर से छूट दी जाएगी बशर्ते कि वह निम्नलिखित द्वारा प्राप्त किया गया हो या उनका उस पर हितभागी स्वामित्व हो,

(i) दूसरे सविदाकारी राज्य की सरकार, राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण, अथवा

(ii) दूसरे सविदाकारी राज्य का सेंट्रल बैंक।

(ख) एक सविदाकारी राज्य में अर्जित होने वाले ब्याज का उस राज्य में कर से छूट दी जाएगी यदि उस पर दूसरे सविदाकारी राज्य के निवासी का हितभागी स्वामित्व हो और वह निम्न-लिखित द्वारा दिए गए अथवा समर्थित ऋण अथवा उधार के संबंध में प्राप्त किया जाता हो :

(i) बेकोम्पोबाकिया के मामले में बेकोम्पोबॉरका ओवरोडनी बैंक, जिन सीमा तक ऐसा ब्याज केवल आयातों-निर्यातों की वित्तीयव्यवस्था करने के कारण होता है,

(ii) भारत के मामले में, भारतीय आयात-निर्यात बैंक (एनिसम बैंक) जिस सीमा तक ऐसा ब्याज केवल आयातों-निर्यातों की वित्तीयव्यवस्था करने के कारण होता है,

(iii) किसी सविदाकारी राज्य के विदेशी व्यापार की सार्वजनिक वित्त व्यवस्था करने वाला कोई संस्थान,

(iv) कोई भी अन्य व्यक्ति बशर्ते कि ऋण अथवा उधार प्रयोजनोन्मुखित सविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा अनुमोदित हो।

4. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "ब्याज" शब्द से अभिप्रेत है प्रत्येक प्रकार के ऋण संबंधी दावों से प्राप्त आय, चाहे वह बंधक द्वारा प्रतिभूत हो अथवा नहीं और चाहे ऋणदान के लाभों में भारीवारी का अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं, और खास तौर पर सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय और बन्ध-पत्रों अथवा ऋण-पत्रों जिनमें ऐसी प्रतिभूतियों, बन्ध-पत्रों अथवा ऋण पत्रों के संबंध में प्रदान किए जाने वाले प्रीमियम और पुरस्कार शामिल हैं, से प्राप्त आय। निम्नलिखित अदायगी के लिए अर्पण्डण सम्बन्धी प्रभावों को इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए ब्याज नहीं समझा जाएगा।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबन्ध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि ब्याज का हितभागी स्वामी, सविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते दूसरे सविदाकारी राज्य जिसमें ब्याज अर्जित हुआ हो, स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से व्यापार करता है, अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित एक निश्चित स्थान से वहां स्वतन्त्र वैयक्तिक सेवाएं करता है और जिस ऋण-दावे के बारे में ब्याज अदा किया जाता है, वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बन्धित है। इस प्रकार के मामले में, अनुच्छेद 7 अथवा 14 के उपबन्ध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

6. किसी सविदाकारी राज्य में ब्याज, उत्पन्न हुआ माना जाएगा, यदि ब्याज अदा करने वाला स्वयं वह सविदाकारी राज्य कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस राज्य का निवासी हो। किन्तु, जहां ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह सविदाकारी राज्य का निवासी हो, अथवा नहीं, सविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान हो, जिसके संबंध में वह ऋण लिया गया था जिस पर ब्याज की अदायगी की गई है, और इस प्रकार का ब्याज उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया है, तब वह ब्याज उस सविदाकारी राज्य में उत्पन्न हुआ माना जाएगा जिनमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

7. जहां, ब्याज अदा करने वाले और हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों के बीच तथा किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष सम्बन्ध होने के कारण, अदा की गयी ब्याज की रकम, उस ऋण-दावे को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए ब्याज की रकम अदा की गयी है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके संबंध में, इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में, अदा करने वाले और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गयी होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबन्ध अन्तिम वर्णित रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदायगी के अतिरिक्त भाग पर, इस प्रकार के अन्य उपबन्धों का सम्यक् अनुपालन करते हुए, प्रत्येक सविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद-12

रायल्टियों और तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क

1. एक सविदाकारी राज्य में उत्पादित होने वाली और दूसरे सविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गयी रायल्टियों तथा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. लेकिन, इस प्रकार की रायल्टियों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर भी उस सविदाकारी राज्य में तथा उस राज्य के कानूनों के अनुसार भी कर लगाया जा सकेगा जिसमें ये उत्पन्न हुये हों। परन्तु यदि प्राप्तकर्ता रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी हो तो इस प्रकार प्रभावित कर, रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की सकल रकम के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "रायल्टियों" शब्द से अभिप्रेत है किसी साहित्यिक, कलात्मक तथा वैज्ञानिक वृत्तियों, जिसमें चलचित्र फिल्मों अथवा रेडियो अथवा दूरदर्शन प्रसारण के लिए फिल्मों अथवा टेपों के प्रतिनिध्याधिकार, कोई पेटेंट, ट्रेड मार्क, डिजाइन अथवा माडल, प्लान ग्लस कार्मुला अथवा प्रशिक्षण के प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगाधिकार के लिए अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपस्कर अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुसंधान से सम्बन्धित जानकारी के प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार के प्रतिकूल के रूप में प्राप्त किसी भी प्रकार की अदायगी।

4. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" पद से अभिप्रेत है प्रबन्धकीय, तकनीकी अथवा परामर्शदात्री स्वरूप की सेवाओं, जिनमें तकनीकी अथवा अन्य कामों की सेवाओं की व्यवस्था

भी शामिल है, के प्रतिफल में, प्रदायगियों करने वाले व्यक्ति के कर्मचारी को की गई प्रदायगियों से भिन्न, किसी भी व्यक्ति को की गई किसी भी रकम की प्रदायगियां।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी, जो जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है और उस दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क उत्पन्न होते हैं, वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतन्त्र वैयक्तिक सेवाएं करता है और जिस अधिकार, सम्पत्ति अथवा संविदा के कारण रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस भ्रवा की जाती है, वे ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बन्धित है, 1 ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

6. रायल्टियों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस किसी संविदाकारी राज्य में उत्पन्न हुए माने जाएंगे यदि भ्रवा करने वाला स्वयं वह राज्य कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो। परन्तु, जहां रायल्टियां और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस भ्रवा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान हो जिसके संबंध में रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस भ्रवा करने का दायित्व बना हो, और इस प्रकार की रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा बहन की जाती हों तो इस प्रकार की रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस राज्य में उत्पन्न हुई समझी जाएगी जिसमें स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित हो।

7. जहां, अशक्तता और हितभागी स्वामी अथवा उन दोनों के बीच तथा किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण, रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए भ्रवा की गई फीस की रकम, उस रकम से बढ़ जाती है जो इस प्रकार का सम्बन्ध नहीं होने की स्थिति में भ्रवा की गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम वर्णित रकम पर ही लागू होंगे। ऐसी स्थिति में, प्रदायगियों के अतिरिक्त अंश पर, इस प्रकार के अन्य उपबंधों पर समुचित ध्यान देने हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद-13

पूँजीगत लाभ

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा, अनुच्छेद 6 में उल्लिखित तथा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त लाभों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. चल सम्पत्ति के अन्तरण से, जो एक संविदाकारी राज्य के उद्यम की उस स्थायी संस्थापन की व्यापारिक सम्पत्ति के अंग के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित है, अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित चल सम्पत्ति के अंतरण से, जो एक संविदाकारी राज्य के निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतन्त्र वैयक्तिक सेवाओं के निष्पादन के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है, होने वाले लाभों पर, जिसमें ऐसे स्थायी संस्थापन (अथवा अथवा सम्पूर्ण उद्यम के साथ) अथवा ऐसे निर्धारित स्थान के अंतरण से होने वाले लाभ भी शामिल हैं, उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

3. अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में चलाये जाने वाले जलयानों अथवा वायुयानों अथवा इस प्रकार के जलयानों अथवा वायुयानों के परिचालन से संबंधित चल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त लाभ पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका अंतरणकर्ता निवासी है।

4. किसी ऐसी कम्पनी के पूँजी स्टाफ के शेयरों के अंतरण से होने वाले लाभों पर, जिसकी सम्पत्ति प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी संविदाकारी राज्य में स्थित मुख्यतः अचल सम्पत्ति है, उस राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

5. किसी कम्पनी के, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है पैराग्राफ 4 में उल्लिखित शेयरों से भिन्न शेयरों के अंतरण से होने वाले लाभों पर उस राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

6. पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 तथा 5 में उल्लिखित सम्पत्ति से भिन्न सम्पत्ति के अंतरण से होने वाले लाभों पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका अंतरणकर्ता निवासी है।

अनुच्छेद-14

स्वतन्त्र व्यक्तिगत सेवाएं

1. किसी व्यक्ति द्वारा जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, व्यावसायिक सेवाओं अथवा उसी प्रकार के दूसरे स्वतन्त्र कार्यकलापों में निष्पादन से प्राप्त आय निम्नलिखित परिस्थितियों के सिवाय जब ऐसी आय पर भी दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा, केवल उसी राज्य में कर लगने योग्य होगी :

(क) यदि उसे अपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध हो, उस स्थिति में, केवल उसकी उत्तरी आय पर ही उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा जितनी कि उस निश्चित स्थान के कारण हुई मानी जा सकती हो; अथवा

(ख) यदि उस दूसरे राज्य में उसकी उपस्थिति संगत "पिछले वर्ष अथवा आय वर्ष" में, जैसी भी स्थिति हो, कुल मिलाकर 90 दिनों की अवधि या अवधियों अथवा उससे अधिक की अवधियों की हो, तो उस स्थिति में उस दूसरे राज्य में केवल उत्तरी आय पर ही कर लग सकेगा जितनी कि उस दूसरे राज्य में किये गये उसके कार्यकलापों से प्राप्त हुई हो।

2. "व्यक्ति सेवाएं" पद में स्वतन्त्र वैज्ञानिक साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षणिक अथवा अध्यापन संबंधी कार्यकलाप तथा कार्य-व्यक्तिसकों, शिल्प चित्रकारों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तुकारों, दंतचिकित्सकों और लेखा-कारों के स्वतन्त्र कार्यकलाप शामिल हैं।

अनुच्छेद-15

पराश्रित वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुच्छेद 16, 17, 18, 19, 20 तथा 21 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त बैठन, मजदूरी तथा इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर तब तक केवल उसी राज्य में कर लग सकेगा जब तक कि नियोजन उस दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं किया जाता। यदि इस प्रकार नियोजन किया जाता है तो उससे प्राप्त होने वाले ऐसे पारिश्रमिक पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होने हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर कर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही लग सकेगा यदि :

(क) प्राप्तकर्ता संगत "पिछले वर्ष" अथवा "आय वर्ष" में, जैसी भी स्थिति हो, कुल मिलाकर 183 दिन से अनधिक की अवधि अथवा अवधियों के लिए दूसरे राज्य में मौजूद रहा हो; और

(ख) पारिश्रमिक की प्रदायगी ऐसे नियोजक द्वारा अथवा की ओर से की गई हो जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है; और

(ग) पारिश्रमिक किसी ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थापन द्वारा वृद्ध नहीं किया जाता है जो नियोजन का दूसरे राज्य में है।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, संविदाकारी राज्य के किसी उच्चम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यातायात में परिवारित किसी जलयान अथवा वायुयान पर किए गए नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

अनुच्छेद-16

निदेशकों की फीस तथा उच्चस्तर के प्रबंधकीय

अधिकारियों का पारिश्रमिक

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी ऐसी कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्य की हैसियत में, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, प्राप्त निदेशक की फीस तथा इसी प्रकार की अन्य अदायगियों पर उसे दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा।

2. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी ऐसी कंपनी के उच्चस्तर के प्रबंधकीय पद के अधिकारी की हैसियत में, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, प्राप्त वेतन, मजदूरी तथा इसी प्रकार के दूसरे पारिश्रमिक पर उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

अनुच्छेद - 17

कलाकार और खिलाड़ी

1. अनुच्छेद 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी, लोक मनोरंजनकर्ताओं (जैसे कि रंगमंच, चलचित्र, रेडियो अथवा दूरदर्शन कलाकारों, संगीतकारों) अथवा खिलाड़ियों द्वारा अपने इस प्रकार के वैयक्तिक कार्यकलापों से प्राप्त आय पर कर केवल उस संविदाकारी राज्य में लगाया जा सकेगा जिसमें ये कार्यकलाप किये जाते हैं।

बशर्ते कि ऐसी आय पर उक्त संविदाकारी राज्य में कर नहीं लगाया जाएगा यदि लोक मनोरंजनकर्ताओं अथवा खिलाड़ियों के उस राज्य के दौर का छात्रा प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पूर्णतः अथवा पर्याप्त रूप से दूसरे संविदाकारी राज्य की सार्वजनिक निधि में पूरा किया गया हो।

2. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ "सार्वजनिक निधि" पद का तात्पर्य एक संविदाकारी राज्य की अथवा उसके राजनीतिक उप-मंडल अथवा स्थानीय या गांधिक प्राधिकरणों की निधि से है।

अनुच्छेद-18

सरकारी सेवा के संबंध में

पारिश्रमिक तथा पेंशन

1. (क) एक संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उपमंडल अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को उस राज्य अथवा उपमंडल अथवा प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के संबंध में अदा किए गए पेंशन से विभिन्न पारिश्रमिक पर कर केवल उस राज्य में ही लगाया जा सकेगा।

(ख) तथापि, ऐसे पारिश्रमिक पर केवल उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा यदि सेवाएं उस दूसरे राज्य में की जाती हैं तथा व्यक्ति उस राज्य का निवासी है जो

- (1) उस राज्य का राष्ट्रिक है, अथवा
- (2) मात्र सेवाएं करने के प्रयोजनार्थ उस राज्य का निवासी नहीं बना।

2. (क) किसी संविदाकारी राज्य के अथवा उसके राजनीतिक उपमंडल अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण के लिए की गयी सेवाओं के संबंध में उस राज्य अथवा उपमंडल अथवा स्था-

नीय प्राधिकरण द्वारा अथवा उनके द्वारा सृजित निधियों से किसी व्यक्ति को की गई किसी भी पेंशन पर केवल उस राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा।

(ख) तथापि, ऐसी पेंशन पर केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा यदि वह व्यक्ति उस दूसरे राज्य का निवासी तथा राष्ट्रिक है।

3. अनुच्छेद 15, 16 तथा 17 के उपबंध एक संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-मंडल अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाए गए कारबार के संबंध में की गई सेवाओं के बारे में प्राप्त पारिश्रमिक और पेंशन पर लागू होंगे।

अनुच्छेद - 19

गैर सरकारी पेंशन तथा वार्षिकी

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के अंतर्गत के स्वतंत्रों से प्राप्त की जा रही, अनुच्छेद 18 में उल्लिखित पेंशन से भिन्न, किसी पेंशन, अथवा किसी वार्षिकी पर कर केवल प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में लगाया जा सकेगा।

2. "पेंशन" शब्द का अर्थ उस नियतकालिक भुगतान से है जो बिगत समय में की गई सेवाओं के प्रतिफल के रूप में अथवा सेवाओं के निष्पादन के दौरान शारीरिक चोट की क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त किया गया हो।

3. "वार्षिकी" शब्द का अर्थ उस उल्लिखित राशि से है जो धन अथवा धन के मूल्य में पर्याप्त अथवा पूरे प्रतिफल के लिए अदायगियां करने के किसी दायित्व के अधीन जीवनपर्यन्त अथवा विनिश्चित अथवा निश्चित समयावधि के दौरान उल्लिखित समय पर देय होगी।

अनुच्छेद - 20

विद्यार्थी और प्रशिक्षु

1. कोई व्यक्ति, जो संविदाकारी राज्यों में से एक का निवासी है तथा दूसरे संविदाकारी राज्य में केवल निम्नलिखित कारणों से अस्थायी रूप से :-

(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा विद्यालय के छात्र के रूप में; अथवा

(ख) व्यापारिक प्रशिक्ष के रूप में, अथवा

(ग) सरकारी धार्मिक, पृथ्वार्थ, वैज्ञानिक, साहित्यिक अथवा शैक्षणिक संगठन से अध्ययन अथवा शोध कार्य के मूल प्रयोजनार्थ अनुदान, भत्ते अथवा पुरस्कार प्राप्तकर्ता के रूप में, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में मीजुद रहता है, उस पर उस दूसरे राज्य में :-

(कक) उसके भरण-पोषण, शिक्षा, प्रशिक्षण, अध्ययन अथवा शोध कार्य के प्रयोजनार्थ खिर्शों से प्राप्त रकमों पर, तथा,

(खख) अनुदान भत्ते अथवा पुरस्कार पर कर नहीं लगाया जाएगा।

2. इस अनुच्छेद तथा अनुच्छेद 21 के प्रयोजनार्थ, किसी व्यक्ति को एक संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा यदि वह उस संविदाकारी राज्य का उस "पिछले वर्ष" अथवा "कैलिण्डर वर्ष" में, जैसी भी स्थिति हो, जिसमें वह दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करता अथवा तत्काल पूर्ववर्ती "पिछले वर्ष" अथवा "कैलिण्डर वर्ष" में निवासी रहा हो।

अनुच्छेद - 21

प्राध्यापक, अध्यापक तथा शोध छात्रों द्वारा
प्राप्त आयसिद्धि

1. किसी प्राध्यापक अथवा अध्यापक को, जो दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी विभवविशालय, महाविशालय, विशालय अथवा दूसरी मान्यताप्राप्त संस्था में अध्यापन कार्य अथवा शोध कार्य करने अथवा दोनों के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करने से तत्काल पूर्व संविदाकारी राज्यों में से एक राज्य का निवासी है अथवा था, ऐसे अध्यापन अथवा शोध कार्य के लिए किसी भी पारिश्रमिक पर उस दूसरे राज्य में उसके पहुँचने की तारीख से 2 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कर से छूट प्राप्त होगी।

2. यह अनुच्छेद शोध कार्य से प्राप्त आय पर लागू नहीं होगा यदि ऐसा शोध कार्य मुख्यतः किसी विशिष्ट व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए किया जाता है।

3. पैराग्राफ 1 के प्रयोजनार्थ, "मान्यता प्राप्त संस्था" का अर्थ ऐसी संस्था से है जिसे संबंधित संविदाकारी राज्य के मन्त्रिमंडल प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अनुमोदित किया गया हो।

अनुच्छेद - 22

अन्य आय

1. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए भी एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की वे मदें, जहाँ-कहाँ उद्भूत होती हों, जिन पर इस करार के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विशेष रूप से विचार नहीं किया गया है, केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लग योग्य होंगी।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथा परिभाषित अचल संपत्ति से प्राप्त होने वाली आय से भिन्न आय पर लागू नहीं होंगे, यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता, एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण, दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उसमें कारबार करता है अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित निश्चित स्थान में स्वतन्त्र व्यक्तिगत सेवाएँ निष्पादित करता है और जिस अधिकार अथवा संपत्ति के संबंध में आय अदा की जाती है वह ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से प्रसिद्ध है। ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे।

3. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की उन मदों पर, जिनका इस करार के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है और जो दूसरे संविदाकारी राज्य में उद्भूत होती हैं, कर उस दूसरे राज्य में लगाया जा सकेगा।

अनुच्छेद - 23

दोहरे कराधान का अपाकरण

1. दोनों की संविदाकारी राज्यों में लागू कानून अपने-अपने संविदाकारी राज्यों में आय के कराधान को शामिल करते रहेंगे मित्रांतर इससे कि जहाँ इस करार में उनके प्रतिकूल कोई उपबंध बनाये जाते हैं।

2. दोनों संविदाकारी राज्य में दोहरे कराधान का परिहार निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा :

(क) जहाँ एक संविदाकारी राज्य का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है, जिस पर, इस करार के उपबंधों के अनुसार, दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, वहाँ

प्रथमोल्लिखित राज्य, इस पैराग्राफ के उपपैरा (ख) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसी आय को कर से छूट दे सकता है परन्तु उस व्यक्ति की शेष आय पर कर की संगणना करने में कर की वह दर लागू कर सकता है जो उस स्थिति में लागू होती यदि छूट प्राप्त आय पर इस प्रकार की छूट नहीं दी गयी होती।

(ख) दोनों ही संविदाकारी राज्य अपने निवासियों पर कर लगाने समय, कर के उस आधार में जिस पर इस प्रकार के कर लगाये जाते हैं, आय की उन मदों को शामिल कर सकेंगे जिन पर इस करार के अनुच्छेद 10, 11 तथा 12 के उपबंधों के अनुसार दूसरे राज्य में भी कर लगाया जा सकता है लेकिन ऐसे आधार पर संगणित कर की राशि में से दूसरे संविदाकारी राज्य में अदा की गई कर की राशि के बराबर की कटौती होंगे। तथापि, ऐसी कटौती प्रथमोल्लिखित राज्य द्वारा लगाए जाने योग्य कर के उस भाग से अधिक नहीं होगी, जैसा कि कटौती मंजूर करने से पहले संगणित किया गया हो जो उस आय के अनुकूल हो जिस पर इस करार के अनुच्छेद 10, 11, 12 के उपबंधों के अनुसार दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

3. पैराग्राफ 2 के उपपैराग्राफ (ख) के प्रयोजनार्थ, "दूसरे संविदाकारी राज्य में अदा किया गया कर" पत्रावली में ऐसी कोई भी रकम शामिल की गयी मानी जाएगी जो दूसरे संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त आय के कराधान से संबंधित कानूनों के अंतर्गत कर लगने योग्य आय की संगणना करने में अनुमत कटौती अथवा छूट अथवा कर की कटौती अथवा अन्यथा रूप में किसी राजन के नहीं होने की स्थिति में देय होती।

अनुच्छेद - 24

सम-व्यवहार

1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रियों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसे किसी कराधान अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान से और उन संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो, जो उस दूसरे राज्य के निवासी राष्ट्रियों पर ऐसी ही परिस्थितियों में अथवा वैसी ही शर्तों के अधीन लागू होती है अथवा हो सकती है।

2. किसी स्थायी संस्थापन पर, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम का दूसरे संविदाकारी राज्य में है, उस दूसरे राज्य में ऐसा कोई कर नहीं लगाया जाएगा जो उस दूसरे राज्य में उन्हीं परिस्थितियों में तथा वैसी ही शर्तों के अधीन वही कार्यकलाप करने वाले उद्यमों पर लगाए जाने वाले कराधान के अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो।

3. इस अनुच्छेद में निहित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह एक संविदाकारी राज्य को, कराधान के प्रयोजनों के लिए, उस राज्य के अनिवासी व्यक्तियों को कोई ऐसी व्यक्तिगत छूटें, राशियाँ तथा कटौतियाँ प्रदान करने के लिए बाध्य करता है जो कानून द्वारा उस राज्य के निवासी व्यक्तियों को ही उपलब्ध है।

4. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिनकी पूर्ण पूर्णतः अथवा अंशतः दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों के, प्रत्यक्ष, अथवा अप्रत्यक्ष स्वामित्व अथवा नियंत्रण में है, प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में कोई ऐसा कराधान अथवा तत्संबंधी कोई ऐसी चीज अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो, जो उस प्रथमोल्लिखित राज्य के अन्य वैसे ही उद्यमों पर उन्हीं परिस्थितियों तथा वैसी ही शर्तों पर लागू होती है अथवा हो सकती है।

5. इस अनुच्छेद में, "कराधान" पद से वे कर अभिप्रेत हैं जो इस करार के विषय हैं।

अनुच्छेद-25

पारस्परिक करार कार्यविधि

1. जहाँ एक संविदाकार राज्य का कोई निवास, यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के कार्यों के कारण उस पर जोर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा वह इस करार के अन्तर्गत नहीं है, तो वह इन दोनों राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों द्वारा उपबंधित उपचारों के होते हुए भी अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह निवासी है। यह मामला, उस कार्यवाही के नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीन वर्ष के भीतर अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके कारण ऐसा कर लगाया गया हो जो इस करार के अन्तर्गत नहीं है।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी उपयुक्त हल पर पहुँचने में असमर्थ हो तो वह ऐ- कराधान के परिहार की दृष्टि से, जो इस अधिसमय के अन्तर्गत नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी की परस्पर सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा। जो भी करार हो गया हो, उसे संविदाकारी राज्यों के कानूनों में निहित किसी भी समय-सीमा के होने के बावजूद भी कार्यान्वित किया जाएगा।

3. इस अधिसमय की व्याख्या करने अथवा इसे लागू करने में यदि कोई कठिनाइयाँ अथवा रुकावट उत्पन्न हों तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे। वे ऐसे मामलों में दोहरे कराधान को दूर करने के लिए परस्पर परामर्श कर सकेंगे जिनकी इस करार में व्यवस्था नहीं की गई है।

4. पूर्वोक्त पैराग्राफों के अभिप्राय के अंतर्गत सहमति के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक-दूसरे के साथ सीधे पत्र व्यवहार कर सकते हैं। जब किसी समझौते पर पहुँचने के लिए विचारों का मौखिक आदान-प्रदान करना उपयुक्त प्रतीत होता हो, वहाँ ऐसा आदान-प्रदान एक आयोग के जरिए किया जा सकता है जिसमें संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधि हों।

अनुच्छेद-26

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी इस करार के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अथवा कर अपव्ययन अथवा करों के परिहार को रोकने अथवा उभार पना भगाने के लिए, जो इस करार के विषय हैं, इस प्रकार की सूचना अथवा दस्तावेजों का, जो आवश्यक हों, आदान-प्रदान करेंगे। उस प्रकार आदान-प्रदान की गई विधियों में सूचना अथवा दस्तावेज को गुप्त समझा जाएगा परन्तु उन्हें ऐसे व्यक्तियों (जिनमें न्यायालय अथवा प्रशासनिक निकाय सम्मिलित हैं) के समक्ष प्रकट किया जा सकता है जो उन करों के निर्धारण, वसूल, प्रवर्तन, जांच अथवा अभिव्यक्ति से या उनमें संबंधित किसी शोखाधर्मी से संबंधित हो, जो इस करार के विषय हैं, या ऐसे व्यक्तियों को जिनसे इस सूचना या प्रलेख का संबंध है।

2. सूचना अथवा दस्तावेजों का आदान-प्रदान या तो नेमी आधार पर अथवा किन्हीं विनिष्ट भाग्यों में अनुरोध मिलने पर किया जाएगा। संविदाकारों राज्यों के सक्षम प्राधिकारी समय-समय पर परस्पर यह तय करेंगे कि किस-किस सूचना का या किन-किन दस्तावेजों का नेमी आधार पर आदान-प्रदान किया जायगा।

3. किसी भी स्थिति में, पैराग्राफ 1 के उपबंधों का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वे एक संविदाकार राज्य को निम्नलिखित कार्य करने के लिए बाध्य करते हैं :-

(क) उन संविदाकारी राज्य अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों अथवा प्रशासनिक परिपाटी से हट कर कोई प्रशासनिक उपाय करना,

(ख) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज सफाई करना जो उस राज्य अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अन्तर्गत अथवा सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया के दौरान प्राप्त नहीं हो सकते।

(ग) कोई ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज सफाई करना जिससे कोई व्यापारिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वृत्तिक भेद खल जाएगा अथवा कोई व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना जिनको प्रकट करना मार्कजिनिक नीति के विपरीत होगा।

अनुच्छेद-27

राजनयिक तथा कौमुली अधिकारी

इस करार में निहित किसी व्यवस्था का, अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सामान्य नियमों के अन्तर्गत अथवा विशेष करारों के उपबंधों के अंतर्गत राजनयिक अथवा कौमुली अधिकारियों के वितीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुच्छेद-28

प्रवर्तन

प्रत्येक संविदाकारी राज्य दूसरे संविदाकारी राज्य को इस करार को प्रवर्तित करने के लिए उसके कानून के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यविधियों के पुरा हो जाने के बारे में अधिसूचित करेगा। यह करार, इन अधिसूचनाओं में से बाद वाले अधिसूचना की तारीख की लागू होगा और उसके बाद :

(क) भारत में, अप्रैल, 1985 के प्रथम दिन अथवा उसके बाद से किसी पूर्ववर्ती वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के सम्बन्ध में;

(ख) चेकोस्लोवाकिया में, जनवरी, 1985 के प्रथम दिन अथवा उसके बाद से किसी आय वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के सम्बन्ध में, लागू होगा।

अनुच्छेद-29

समाप्ति

यह करार अनिवार्यतः समय तक लागू रहेगा परन्तु दोनों में से कोई भी संविदाकारी राज्य इस करार के लागू होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि पूरी हो जाने के पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी भी कैलेंडर वर्ष के 30 जून को अथवा उसके पूर्व राजनयिक माध्यमों से, दूसरे संविदाकारी राज्य को मनाप्ति का लिखित नोटिस दे सकता है और ऐसी स्थिति में यह करार :

(क) भारत में, जिस कैलेंडर वर्ष में नोटिस दिया जाता है उसके अगले परवर्ती वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी पूर्ववर्ती वर्ष में उद्भूत होने वाले आय के सम्बन्ध में;

(ख) चेकोस्लोवाकिया में, जिस कैलेंडर वर्ष में समाप्ति का नोटिस दिया जाता है उसके अगले परवर्ती वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी आय वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के सम्बन्ध में, निष्प्रभावी हो जाएगा।

जिनके माध्यम से, इसके लिए विनिष्ट प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किये हैं।

नई दिल्ली में वर्ष एक हजार तीसरी शताब्दी के जनवरी मास के 27 वें दिन अंग्रेजी भाषा में दो प्रतियों में सम्पन्न हुआ।

(विश्वनाथ प्रताप सिंह)

वित्त मंत्री

भारत सरकार की ओर से

(हंग जारोमीर जाक)

वित्त मंत्री

चेकोस्लोवाकिया समाजवादी गणराज्य की सरकार की ओर से

प्रोतीकोन

राज के दिन भारत सरकार तथा चेकोस्लोवाकिया समाजवादी गणराज्य की सरकार के बीच आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान का परिहार तथा वित्तीय अपव्ययन के निवारण के लिए किए गए करार पर हस्ताक्षर करते समय अधोदस्ताक्षरी पूर्वाधिकारों एवं शर्तों पर सहमत है कि निम्नलिखित उपबंध करार के अनिवार्य भाग होंगे।

1. अनुच्छेद 7 (स्थापने से स्थापन)

- (i) पैराग्राफ 2 के खंड (छ) में यथा प्राकृत "संयोजन परियोजना" पद में उपकरण की संस्थापना शामिल है।
- (ii) पैराग्राफ 3 के खंड (क) तथा (ख) के उपबंध अलग-अलग संविदा की अवधि के दौरान ऐसे मामले में उपयुक्त परिवर्तन के साथ लागू होंगे, जहाँ मुविद्याओं का प्रयोग अथवा मालअथवा निजागर्त भाग के संस्थापना का रखरखाव, अण्डारण अथवा नदरीत के अनिवार्य, संविदाकारी राज्य में संस्थापित माल के स्टॉक से प्रतिस्थापन के जरिए फालतू पुर्जों तथा उपार्गों की सुपुर्दगी के प्रयोजनार्थ है।

11. अनुच्छेद 8 (हवाई यातायात)

अनुच्छेद 28 में किसी बात के होते हुए, हवाई यातायात से सम्बन्धित अनुच्छेद 8 के उपबंध 1 जनवरी, 1961 से लागू होंगे तथा यदि कोई कर अथवा किया गया हो तो उसे इस करार के लागू होने की तारीख से वापस करने के भीतर आवेदन करने पर वापस किया जाएगा।

(विश्वनाथ प्रताप सिंह)

(हंग गारोमर आक)

वित्त मंत्री

वित्त मंत्री

भारत सरकार की ओर से

चेकोस्लोवाकिया समाजवादी गणराज्य की सरकार की ओर से

14 अप्रैल, 1986

सं. पी. आर. ए./204/2/86-पी. सी. एम.

भारतीय राजदूतावास चेकोस्लोवाकिया समाजवादी गणराज्य की सरकार के वित्त मंत्रालय का अभिनन्दन करता है और भारत सरकार और चेकोस्लोवाकिया समाजवादी गणराज्य की सरकार के बीच आय पर करों के सम्बन्ध में दोहरे कराधान के परिहार तथा वित्तीय अपव्ययन को रोकने के लिए 27 जनवरी, 1987 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित करार के अनुच्छेद 28 के संदर्भ में यह समुचित करता है कि भारत सरकार ने उक्त करार को लागू करने के लिए आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी कर ली हैं।

2. तदनुसार, भारतीय राजदूतावास चेकोस्लोवाकिया समाजवादी गणराज्य की सरकार को यह भी सूचित करता है कि उक्त करार अभी लागू होगा जब चेकोस्लोवाकिया समाजवादी गणराज्य की सरकार की बात की पृष्टि करते हुए इस प्रकार का एक दिव्यान् भेजे कि चेकोस्लोवाकिया समाजवादी गणराज्य की सरकार ने भी उक्त करार के अनुच्छेद 28 के संदर्भ में औपचारिकताएँ पूरी कर ली हैं।

3. भारतीय राजदूतावास को चेकोस्लोवाकिया समाजवादी गणराज्य की सरकार के संघीय विदेश मंत्रालय को पुनः स्मरण कराने का अवसर प्राप्त हुआ है कि इस आवश्यकता को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

(मोहर)

भारतीय राजदूतावास प्राग

संघीय विदेश मंत्रालय

चेकोस्लोवाकिया समाजवादी गणराज्य प्राग।

संख्या 1042/87

चेकोस्लोवाकिया समाजवादी गणराज्य का राजदूतावास भारत के विदेश मंत्रालय, भारत सरकार का अभिनन्दन करता है और यह अधि-

सूचित करता है कि चेकोस्लोवाकिया समाजवादी गणराज्य की सरकार और भारतीय गणराज्य की सरकार के बीच आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा वित्तीय अपव्ययन को रोकने के लिए दिनांक 27 जनवरी, 1986 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित करार को उक्त करार के अनुच्छेद 28 में तयान्वित वैधानिकता के विधि विनियमों के अनुसार विधिवत अनुमोदित कर दिया गया है।

चेकोस्लोवाकिया समाजवादी गणराज्य के राजदूतावास को भारतीय गणराज्य की सरकार के विदेश मंत्रालय को पुनः स्मरण कराने का अवसर प्राप्त हुआ है कि इस आवश्यकता को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1987

(मोहर)

चेकोस्लोवाकिया

समाजवादी गणराज्य का राजदूतावास

विदेश मंत्रालय,
भारत सरकार
नई दिल्ली:

[सं. 7311 का. सं. 11/22/66-वि. क. प्र.]

ब. यू. इराडा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Foreign Tax Division)

New Delhi, the 25th May, 1987

NOTIFICATION

INCOME-TAX

G.S.R. 526 (E) —Whereas the Government of India and the Government of the Czechoslovak Socialist Republic have concluded an Agreement as set out in the Annexure hereto, for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income;

And whereas all the requirements have been completed in India and Czechoslovakia as are necessary to give the said Agreement the force of law in India and Czechoslovakia respectively, as required by Article 28 of the said Agreement;

And whereas the diplomatic notices to this effect have been exchanged between the said two Governments, as required by Article 28 of the said Agreement;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and section 24A of the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Agreement shall be given effect to in the Union of India.

ANNEXURE

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF INDIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE CZECHOSLOVAK SOCIALIST REPUBLIC

FOR

THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of India and the Government of the Czechoslovak Socialist Republic,

Desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,

Have agreed as follows :

Article 1

PERSONAL SCOPE

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

TAXES COVERED

1. The taxes to which this Agreement shall apply are :

(a) In the case of India :

(1) the income-tax including any surcharge thereon imposed under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961);

(2) the surtax imposed under the Companies (Profits) Surtax Act, 1961 (7 of 1964) ;

(hereafter referred to as "Indian tax")

(b) In the case of Czechoslovakia :

(1) the taxes on profits ;

(2) the wages tax ;

(3) the tax on income from literary and artistic activities ;

(4) the agricultural tax ;

(5) the tax on population income ;

(6) the house tax ;

(hereafter referred to as "Czechoslovak tax").

2. The Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed by either Contracting State after the date of signature of the present Agreement in addition to, or in place of, the taxes referred to in paragraph 1 of this Article.

3. At the end of each year, the competent authorities of the Contracting States shall notify to each other any significant changes which have been made in their respective laws governing the taxes which are the subject of this Agreement and furnish copies of relevant enactments and regulations.

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. In this Agreement, unless the context otherwise requires :

(a) the term "India" means the territory of India and includes the territorial sea and airspace above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights, other rights and jurisdictions, according to the Indian law and in accordance with international law [U. N. Convention on the Law of the Sea ;

(b) the term "Czechoslovakia" means the Czechoslovak Socialist Republic ;

(c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean India or Czechoslovakia, as the context requires ;

(d) the term "tax" means Indian tax or Czechoslovak tax, as the context requires ;

(e) the term "person" shall have the meaning assigned to it in the taxation laws in force in the respective Contracting States ;

(f) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a company under the taxation laws of the respective Contracting States ;

(g) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean, respectively, an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State ;

(h) the term "competent authority" means in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue); and in the case of Czechoslovakia, the Minister of Finance of the Czechoslovak Socialist Republic or his duly authorised representative.

2. In the application of the provisions of this Agreement by one of the Contracting States, any term not defined herein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws in force in that Contracting State relating to the taxes which are the subject of this Agreement.

Article 4

FISCAL DOMICILE

1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means any person who is a resident of that Contracting State in accordance with the taxation laws of that Contracting State.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1, an individual is a resident of both Contracting States, then his residential status for the purposes of this Agreement shall be determined in accordance with the following rules : —

(a) He shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations and closer (hereinafter referred to as his "centre of vital interests") ;

(b) If the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he does not have a permanent home available to him in either Contracting

State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode;

- (c) If he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national;
- (d) If he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a resident of both the Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which its place of effective management is situated.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" shall include :

- (a) a place of management;
- (b) a branch;
- (c) an office;
- (d) a factory;
- (e) a workshop or a warehouse;
- (f) a mine, a quarry, an oil field or other place of extraction of natural resources;
- (g) a building site or construction or assembly project or supervisory activities in connection therewith, where such site, project or supervisory activity continues for a period of more than six months, or where such project or supervisory activity, being incidental to the sale of machinery or equipment, continues for a period not exceeding six months and the charges payable for the project or supervisory activity exceed 10 per cent of the sale price of the machinery or equipment.

3. The term "permanent establishment" shall not be deemed to include :

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by an enterprise of the other Contracting State;

- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or for collecting information, for the enterprise;
- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information or for scientific research, being activities solely of a preparatory or auxiliary character, in the trade or business of the enterprise. However, this provision shall not be applicable where the enterprise maintains any other fixed place of business in the other Contracting State for any purpose or purposes other than the purposes herein specified.

4. A person acting in a Contracting State for or on behalf of an enterprise of the other Contracting State — other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies — shall be deemed to be a permanent establishment of that enterprise in the firstmentioned Contracting State if :

- (a) he has and habitually exercises in that Contracting State, an authority to negotiate and enter into contracts for or on behalf of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise; or
- (b) he habitually maintains in the first-mentioned Contracting State a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise from which he regularly delivers goods or merchandise for or on behalf of the enterprise; or
- (c) he habitually secures orders in the first-mentioned Contracting State exclusively or almost exclusively, for the enterprise itself, or for the enterprise and other enterprises which are controlled by it or have a controlling interest in it.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an individual status, where such persons are acting in the ordinary course of their business.

6. The fact that a company, which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other Contracting State (whether through a permanent establishment or otherwise) shall not, of itself, constitute for either company a permanent establishment of the other.

7. An enterprise of a Contracting State shall be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it carries on business which consists of providing the services of public entertainers (such as stage, motion picture, radio or television artists and musicians) or athletes in that other Contracting State unless the enterprise is directly or indirectly supported wholly or substantially, from the public funds of the Government of

the first-mentioned Contracting State in connection with the provision of such services.

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income from immovable property may be taxed only in the Contracting State in which such property is situated.

2. The term "immovable property" shall be defined in accordance with the law and usage of the Contracting State in which the property is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, oilwells, quarries and other places of extraction of natural resources. Ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraph 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of professional services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to (a) that permanent establishment; (b) sales in that other State of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold through that permanent establishment; or (c) other business activities carried on in that other State of the same or similar kind as those effected through that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment. In any case where the correct amount of profits attributable to a permanent establishment is incapable of determination or the determination thereof presents exceptional difficulties, the profits attributable to the permanent establishment may be estimated on a reasonable basis.

3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, in accordance with the provisions of and subject to the limitation of the taxation laws of that State. However, no such deduction shall be allowed in respect of amounts, if any paid (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents, know-how or other rights, or by way of commission or other charges, for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the permanent establishment. Likewise, no account shall be taken, in the determination of the profits of a permanent establishment, for amounts charged (otherwise than towards reimbursement of actual expenses), by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents, know-how or other rights, or by way of commission or other charges for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the head office of the enterprise or any of its other offices.

4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

5. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

6. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of these Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

AIR TRANSPORT

1. Income derived from the operation of aircraft by an enterprise of one of the Contracting States shall not be taxed in the other Contracting State unless the aircraft is operated wholly or mainly between places within that other Contracting State.

2. Paragraph 1 shall likewise apply in respect of participations in pools of any kind by enterprises engaged in air transport.

3. For the purpose of paragraph 1, interest on funds directly connected with the operation of aircraft in international traffic shall be regarded as income from the operation of such aircraft.

Article 9

ASSOCIATED ENTERPRISES

Where

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Article 10

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends, the tax so charged shall not exceed :

- (a) 15 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which owns at least 25 per cent of the shares of the company paying the dividends;
- (b) 25 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term, "dividends" as used in this article means income from shares or other rights, not being debt-claims participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraph 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid

is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7, or Article 14 as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company except in so far as such dividends are paid to a resident of that other State or so far as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the Company undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2,—

(a) interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State provided it is derived and beneficially owned by :

- (i) the Government, a political sub division or a local authority of the other Contracting State; or
- (ii) the Central Bank of the other Contracting State;

(b) interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State if it is beneficially owned by a resident of the other Contracting State and is derived in connection with a loan or credit extended or endorsed by :

- (i) in the case of Czechoslovakia, the Československá obchodní banka, to the extent is attributable to financing of exports and imports only;
- (ii) in the case of India, the Export-Import Bank of India (Exim Bank), to the extent such interest is attributable to financing of exports and imports only;
- (iii) any institution of a Contracting State in charge of public financing of external trade;
- (iv) any other person provided that the loan or credit is approved by the Government of the first-mentioned Contracting State.

4. The term 'interest' as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt claims in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of such Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 12

ROYALTIES AND FEES FOR TECHNICAL SERVICES

1. Royalties and fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties and fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties, or fees for technical services, the tax so charged shall not exceed 30 per cent of the gross amount of the royalties or fees for technical services.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work, including cinematograph films or films or tapes used for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The term "fees for technical services" as used in this article means payments of any amount to any person other than payments to an employee of a person making payments, in consideration for the services of a managerial, technical or consultancy nature, including the provision of services of technical or other personnel.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties or fees for technical services arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right, property or contract in respect of which the royalties or fees for technical services are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

6. Royalties and fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties or fees for technical services, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties or fees for technical services was incurred, and such royalties or fees for technical services are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of royalties or fees for technical services paid exceeds the amount which would have been paid in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 13

CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property,

referred to in Article 6, and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State, or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or together with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

4. Gains from the alienation of shares of the capital stock of a company the property of which consists directly or indirectly principally of immovable property situated in a Contracting State may be taxed in that State.

5. Gains from the alienation of shares other than those mentioned in paragraph 4 in a company which is a resident of a Contracting State may be taxed in that State.

6. Gains from the alienation of any property other than that mentioned in paragraphs 1, 2, 3, 4 and 5 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State from the performance of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State except in the following circumstances when such income may also be taxed in the other Contracting State :

- (a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities ; in that case, only so much of the income as is attributable to the fixed base may be in that other State; or
- (b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 90 days in the relevant "previous year" or "year of income" as the case may be; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State.

2. The term "professional services" includes independent scientific literary, artistic, educational or teaching activities, as well as the independent activities of physicians, surgeons, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15.

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 16, 17, 18, 19, 20 and 21, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if :

- (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the relevant "previous Year" or "Year of income", as the case may be ; and
- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State ; and
- (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that State.

Article 16

DIRECTORS' FEES & REMUNERATION OF TOP LEVEL MANAGERIAL OFFICIALS

1. Directors' fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the Board of Directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in his capacity as an official in a top-level managerial position of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State

Article 17

ARTISTES AND ATHLETES

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by public entertainers (such as stage, motion picture, radio or television artistes and musicians) or athletes, from their personal activities as much may be taxed only in the Contracting State in which these activities are exercised:

Provided that such income shall not be taxed in the said Contracting State if the visit of the public

entertainers or athletes to that State is directly or indirectly supported, wholly or substantially, from the public funds of the other Contracting State.

2. For the purposes of this Article, the term "public funds" means the funds of a Contracting State or its political sub-divisions, or local or statutory authorities.

Article 18

REMUNERATION AND PENSIONS IN RESPECT OF GOVERNMENT SERVICE

1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or sub-division or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other State and the individual is a resident of that State who :

- (i) is a national of that State ; or
- (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. (a) Any pension paid by, or out of funds created by a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or sub-division or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of that other State.

3. The provisions of Articles 15, 16 and 17 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political sub-division or local authority thereof.

Article 19

NON-GOVERNMENT PENSIONS AND ANNUITIES

1. Any pension, other than a pension referred to in Article 18, or any annuity derived by a resident of a Contracting State from sources within the other Contracting State may be taxed only in the first-mentioned Contracting State.

2. The term "pension" means a periodic payment made in consideration of past services or by way of compensation for injuries received in the course of performance of services.

3. The term "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

312 GI/87-3

Article 20

STUDENTS AND APPRENTICES

1. An individual who is a resident of one of the Contracting State and is temporarily present in the other Contracting State solely, —

- (a) as a student at a recognised university, college or school in that other Contracting State, or
- (b) as a business apprentice, or
- (c) as the recipient of a grant, allowances, or award for the primary purpose of study or research from a governmental, religious, charitable, scientific, literary or educational organisation,

shall not be subjected to tax in that other Contracting State—

- (aa) on the remittances from abroad for the purposes of his maintenance, education, training, study or research, and
- (bb) the grant, allowance or award.

2. For the purposes of this Article and Article 21, an individual shall be deemed to be a resident of a Contracting State if he is resident in that Contracting State in the "previous year" or calendar year, as the case may be, in which he visits the other Contracting State or in the immediately preceding "previous year" of calendar year.

Article 21

PAYMENTS RECEIVED BY PROFESSORS, TEACHERS AND RESEARCH SCHOLARS

1. A professor or teacher who is or was a resident of one of the Contracting States immediately before visiting the other Contracting State for the purpose of teaching or engaging in research, or both, at a university, college, school or other approved institution in that other Contracting State shall be exempt from tax in that other State on any remuneration for such teaching or research for a period not exceeding two years from the date of his arrival in that other State.

2. This Article shall not apply to income from research if such research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.

3. For the purposes of paragraph 1, "approved institution" means an institution which has been approved in this regard by the competent authority of the concerned Contracting State.

Article 22

OTHER INCOME

1. Subject to the provisions of paragraph 2, items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, which are not expressly dealt with in the foregoing Articles of this Agreement, shall be taxable only in that Contracting State

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the State, carries on business in the other Contracting recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement, and arising in the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 23

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. The laws in force in either of the Contracting States will continue to govern the taxation of income in the respective Contracting States except where provisions to the contrary are made in this Agreement.

2. In both the Contracting States, double taxation will be avoided in the following manner :

(a) Where a resident of a Contracting State derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in the other Contracting State, the first-mentioned State shall, subject to the provisions of sub-paragraph (b) of this paragraph, exempt such income from tax but may, in calculating tax on the remaining income of that person, apply the rate of tax which would have been applicable if the exempted income had not been so exempted.

(b) Either of the Contracting States when imposing taxes on its residents may include in the tax base upon which such taxes are imposed the items of income which according to the provisions of Articles 10, 11 and 12 of this Agreement may also be taxed in the other State but shall allow as a deduction from the amount of tax computed on such a base an amount equal to the tax paid in the other Contracting State. Such deduction shall not, however, exceed that part of tax leviable by the first-mentioned State, as computed before the deduction is given, which is appropriate to the income which, in accordance with the provisions of Articles 10, 11, and 12 of this Agreement may be taxed in the other State.

3. For the purposes of sub-paragraph (b) of paragraph 2 the term "tax paid in the other Contracting State" shall be deemed to include any amount which would have been payable as tax but for any relief by way of the deduction allowed in computing the taxable income or an

exemption or a reduction of tax or otherwise under the laws relating to taxation of income in force in that other Contracting State.

Article 24

NON-DISCRIMINATION

1. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which resident nationals of that other State in the same circumstances and under the same conditions are or may be subjected.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities in the same circumstances or under the same conditions.

3. Nothing contained in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to persons not residents in that State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes which are by law available only to persons who are so resident.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected in the same circumstances and under the same conditions.

5. In this Article, the term "taxation" means taxes which are the subject of this Agreement.

Article 25

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Agreement, he may, notwithstanding the remedies provided by the national laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident. This case must be presented within three years of the date of receipt of notice of the action which gives rise to taxation not in accordance with the Agreement.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to avoidance of taxation not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding

any time limits in the national laws of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach an agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article 26

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information or document as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or for the prevention or detection of evasion or avoidance of the taxes which are the subject of this Agreement. Any information or document so exchanged shall be treated as secret but may be disclosed to persons (including a court or administrative body) concerned with the assessment, collection, enforcement, investigation or prosecution in respect of the taxes which are the subject of this Agreement, or any frauds connected therewith, or to persons with respect to whom the information or document relates.

2. The exchange of information or documents shall be either on a routine basis or on request with reference to particular cases. The competent authorities of the Contracting States shall agree from time to time on the list of the information or documents which shall be furnished on a routine basis.

3. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation :

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws or administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to supply information or documents which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- (c) to supply information or documents which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process or information the disclosure of which would be contrary to public policy.

Article 27

DIPLOMATIC AND CONSULAR OFFICIALS

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 28

ENTRY INTO FORCE

Each of the Contracting States shall notify to the other the completion of the procedures required by its law for the bringing into force of this Agreement. This Agreement shall enter into force on the date of the later of these notifications and shall thereupon have effect :

- (a) in India, in respect of income arising in any previous year beginning on or after the first day of April, 1985;
- (b) in Czechoslovakia, in respect of income arising in any year of income beginning on or after the first day of January, 1985.

Article 29

TERMINATION

This Agreement shall remain in force indefinitely but either of the Contracting States may, on or before the thirtieth day of June in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give the other Contracting State through diplomatic channels, written notice of termination and, in such event, this Agreement shall cease to have effect :

- (a) in India, in respect of income arising in any previous year beginning on or after the 1st day of April next following the calendar year in which the notice is given;
- (b) in Czechoslovakia, in respect of income arising in any year of income beginning on or after the 1st day of January next following the calendar year in which the notice of termination is given.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the present Agreement.

Done in duplicate at New Delhi this 27th day of January one thousand nine hundred and eighty six in the English language.

(Vishwanath Pratap Singh)
Finance Minister
For the Government of India

(Ing. Jaromir Zak)
Finance Minister
For the Government of the
Czechoslovak Socialist Republic.

PROTOCOL

At the time of signing the Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on income, this day concluded between the Government of India and the Government of the Czechoslovak Socialist Republic, the undersigned Plenipotentiaries have agreed that the following provisions shall form an integral part of the Agreement.

I. ARTICLE 5 (PERMANENT ESTABLISHMENT).

(i) The term "assembly project" as used in clause (g) of paragraph 2 includes installation of equipment.

(ii) The provisions of clauses (a) and (b) of paragraph 3 shall apply, mutatis mutandis, to a case where the use of facilities or maintenance of stock of goods or merchandise is, in addition to storage or display, for the purpose of delivery of spare parts, and component by way of replacement, during the period of the respective contract, from stock of goods stored in the Contracting State.

II. ARTICLE 8 (AIR TRANSPORT)

Notwithstanding anything contained in Article 28, the provisions of Article 5 relating to Air Transport shall be applicable from 1st January, 1961 and the tax paid, if any, will be refunded on application being made within twelve months of the entry into force of the Agreement.

(Vishwanath Pratap Singh)
Finance Minister.
For the Government of India

(Ing. Jaromir Zak)
Finance Minister
For the Government of the
Czechoslovak Socialist Republic.

No. PRA/204/2/86.Com

14th April, 1986

The Embassy of India presents its compliments to the Federal Ministry of Foreign Affairs, Government of the Czechoslovak Socialist Republic and with reference to Article 28 of the Agreement between the Government of India and the Government of the Czechoslovak Socialist Republic for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion

with respect to taxes on income, signed at New Delhi on the 27th January, 1986, has the honour to state that the Government of India have complied with the requirements necessary for bringing into force of the Agreement.

2. Accordingly, the Embassy has the honour further to state that the aforesaid Agreement will enter into force with a similar note confirming that the Government of the Czechoslovak Socialist Republic have also complied with the requirements of Article 28 of the said Agreement.

3. The Embassy of India avails itself of the opportunity to renew to the Federal Ministry of Foreign Affairs the assurances of its highest consideration.

Federal Ministry of Foreign Affairs.

of the Czechoslovak Socialist Republic,
Prague.

Seal
Embassy of India
Prague.

No. 1042/87.

The Embassy of the Czechoslovak Socialist Republic in India presents its compliments to the Ministry of External Affairs, Government of India, and has the honour to notify that the Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Republic of India for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, signed in New Delhi on 27th January 1986, has been, as required in Article 28 of the said Agreement, duly ratified in accordance with Czechoslovak legal regulations.

The Embassy of the Czechoslovak Socialist Republic avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of External Affairs the assurances of its highest consideration.

New Delhi, March 13, 1987.
Seal

Embassy of the Czechoslovak
Socialist Republic

The Ministry of External Affairs,
Government of India,
New Delhi.

[No. 7311 (F. No. 11/22/66-F.T.D.)]
V. U. ERADI, Jt. Secy.